

भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 3568
दिनांक 21.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

हाल ही में अमेरिकी नीति में हुए बदलाव का प्रवासियों पर प्रभाव

3568. श्रीमती रचना बनर्जी:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) अवैध प्रवासियों के संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका की हाल की नीति में परिवर्तन का उन भारतीय नागरिकों पर क्या संभावित प्रभाव होगा जो वर्तमान में बिना किसी कानूनी दस्तावेज के अमेरिका में रह रहे हैं;
- (ख) अवैध आव्रजन पर अमेरिका के हाल के रुख को भारत सरकार किस प्रकार से देखती है;
- (ग) क्या उक्त नीति परिवर्तन से दोनों देशों के बीच कूटनीतिक चर्चाओं पर प्रभाव पड़ने की संभावना है; और
- (घ) भारत सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारतीय नागरिक, विशेष रूप से अमेरिकी नीति से प्रभावित भारतीय नागरिकों को आवश्यक कानूनी सहायता और सुरक्षा प्राप्त हो, क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
[श्री कीर्तवर्धन सिंह]

(क) से (घ) जिन व्यक्तियों ने अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश किया है, या जो अपनी वीजा वैधता अवधि से अधिक समय तक अमेरिका में रह रहे हैं, या जो बिना किसी वैध दस्तावेज के अमेरिका में रह रहे हैं या जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, उन्हें निर्वासित किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से विदेश में रहते हुए पाया जाता है, तो सभी देशों का यह दायित्व है कि वे अपने नागरिकों को वापस लें। तथापि, यह उनकी राष्ट्रीयता के स्पष्ट सत्यापन के अध्यधीन है। यह केवल

भारत द्वारा अपनाई जाने वाली नीति नहीं है; यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों में आम तौर पर स्वीकृत सिद्धांत है।

अमेरिका पिछले कई सालों से निर्वासन अभियान चला रहा है। अमेरिका से भारतीयों का निर्वासन तभी स्वीकार किया जाता है जब संबंधित भारतीय एजेंसियां लौटने वाले व्यक्तियों की राष्ट्रीयता की पुष्टि कर लेती हैं।

विदेश मंत्रालय सुरक्षित, व्यवस्थित और वैध प्रवास को बढ़ावा देने तथा बेर्इमान एजेंटों, अवैध कार्यों में लिप्त लोगों, आपराधिक गतिविधियों को सहायता प्रदान करने वालों और अवैध आव्रजन नेटवर्क के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके अवैध आव्रजन की समस्या से निपटने के लिए अमेरिकी पक्ष के साथ लगातार संपर्क में है।

भारत सरकार विदेशों में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। इन मुद्दों को हर उपलब्ध अवसर पर विदेशी सरकारों के साथ उठाया जाता है, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार भी शामिल है।

विदेश में रहने वाले भारतीयों को सरकार द्वारा मौजूदा नियमों और नीति के अनुसार आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है।
